अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन परियोजनाओं को प्राथमिकता दे और निर्धारित अवधि में ही इन्हें पूर्ण करे, जिससे देश की गति में अवरोध उत्पन्न न हो।

12.40 hrs.

EXPORT (QUALITY CONTROL AND INSPECTION) AMENDMENT BILL (*Cantd.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri N.R. Laskar on 4th May, 1984, namely :

> "That the Bill to amend the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, be taken into consideration."

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो नियमित (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करता हूं। आज हमारे देश में उद्योग बहुत बढ़ रहे हैं और जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है उसमें 8 हजार से अधिक तैयार माल विदेशों को निर्यात किए जाते हैं तथा काफी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा उसके द्वारा अर्जित की जाती है। फिर भी विदेशी बाजारों में हमारी साख नहीं जम पा रही है जिसका कारण यह है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वह घटिया क्वालिटी का होता है। सरकार को चाहिए कि इस पर पूरा नियन्त्रण करे ताकि जो भी उत्पादन हो वह विश्व मार्केट के लिए उपयोगी हो सके। यह बात निश्चित है कि जब विदेशों में मांग बढ़ेगी तो भारत का विदेशी व्यापार भी बहुत काफी बढ़ेगा। सन् 1960 के अधिनियम में जो त्रुटियां रह गई थीं उनके निवारण के लिए आपने निश्चित रूप से प्रयास किया है। निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) विधेयक को लागू हुए यद्यपि 23 वर्ष बीत चुके हैं परन्तु अभी तक 8 हजार वस्तुओं में से केवल 10 परसेन्ट वस्तुओं पर ही आपका कन्ट्रोल लागू हो सका है (व्यवधान) हमारे पास जो इंफार्मेशन है उसके अनुसार अभी तक जो लिस्ट है उसमें केवल 10 परसेन्ट वस्तुओं पर ही आपका क्वालिटी नियन्त्रण लागू हो सका है। (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि जो भी एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज हैं उनकी क्वालिटी सुधारी जाए। आजकल क्वालिटी प्रोडक्शन का युग है, क्वालिटी प्रोडक्सन की ओर ज्यादा भाग दौड़ है। आज इस देश में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जहां जापान या जर्मनी के द्वारा निर्मित घड़ियों, रेडियो, वी० सी० आर० तथा नाना प्रकार की अन्य चीजों की लालसा न हो। इसलिए आज के युग में क्वालिटी को मेनटेन करना परमावश्यक है। लेकिन हमारे देश में नकल करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। विदेशी चीजों की नकल बनाकर और उन पर जापान आदि की मोहर लगाकर हांगकांग के रास्ते बेचने का यत्न करते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे देश में इस सम्बन्ध में जो निरीक्षण करने वाली सरकारी मशीनरी है वह सही नियन्त्रण नहीं कर रही है। यह जो संशोधन आपने किया है, यह बहुत अच्छा है। इस तरह की अन्धाधुन्ध नकलचीपन की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए आवश्यक था। इसके साथ-साथ निर्यात निरीक्षण परिषद में

सदस्यों की संख्या ग्यारह से पन्द्रह करने जा रहे हैं, इनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि दस सदस्य कम से कम टैक्नालाजी के विशेषज्ञ होने चाहिए। ताकि उत्पादित वस्तुओं का ठीक तरह से निरीक्षण कर सकें। आई०ए०एस० या आई० पी० एस० अधिकारी अच्छे प्रशासक हो सकते हैं, लेकिन उत्पादित वस्तुओं की जानकारी उनको नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कम से कम दस सदस्य टेक्नालाजी के एक्सपर्ट हों ताकि हर वस्तु की क्वालिटी हम सही ढंग से मेनटेन कर सकें। इसी तरह से निरीक्षण परिषद के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण अभिकरण भी सारे देश में बने हुये हैं, लेकिन उनकी व्यापारियों से सांठ-गांठ बनी हुई है। जिसकी वजह से वस्तुयें पास होकर उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इस वजह से एक परेशानी यह होती है कि माल की जो आवश्यकता होती है, उसके अनुसार माल नहीं दिया जाता है। घटिया किस्म का माल होने से कभी-कभी माल वापिस भी हो जाता है। रूस का उदाहरण है और दूसरे देशों का भी उदाहरण हमारे पास हैं। इस दिशा में गलत अधिकारियों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिये। जब एक बार देश की साख बन जाती है, तो फिर वह दोबारा नहीं बन पाती है। आज जापान की साख बनी हुई है, उसकी हर चीज अच्छी है, इलैक्ट्रानिक्स का सामान बहुत अच्छा है। लोग बड़े विश्वास के साथ सामान को खरीद लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस दिशा की ओर सख्त कदम उठाने चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार की मशीनरी में ऐसे एक्सपर्ट हों जो कि कारखाने के कार्य को जाकर समय-समय पर निरीक्षण करें। यदि सामान को बनाने में तकनीकी ज्ञान का अभाव हो, तो उनको पूरा ज्ञान सरकार की ओर से दिया जाना चाहिये। यदि आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता हो तो वह भी दी जानी चाहिये। राष्ट्रीय उत्पादन अच्छा होता है तो विदेशों में हमारे देश का मान होता है और देश की हालत अच्छी होती है। हम अधिक निर्यात करेंगे तो हमें फॉरन एक्सचेन्ज काफी मात्रा में मिल सकेगा। तेल का उत्पादन कम होने की वजह से 600-700 करोड़ रु० का हमें आयात करना पड़ता है, खाद्य पर भी हमें तीन या साढ़े तीन सौ करोड़ हमें खर्च करना पड़ता है। अन्य आवश्यक मदों के लिए भी हमें आयात करना पड़ता है। जिसकी अदायगी हमें फॉरन एक्सचेन्ज में देने में मुश्किल होती है और हम कर्ज में फंस जाते हैं। इस वक्त भी 22 सौ हजार का कर्जा हमारे देश के ऊपर है। यदि हमारा क्वालिटी कन्ट्रोल ठीक ढंग से काम करे और निर्यात की मात्रा में दिन प्रति दिन वृद्धि हो तो हम विदेशी मुद्रा काफी मात्रा में हासिल कर सकते हैं। इससे देश को बड़ा लाभ हो सकता है। इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाता है और जो अधिकारी भेजे जाते हैं उनमें भी राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती है। उत्पादन ठीक से बढ़े और देश समृद्धि की ओर जाए। इसके लिए उनके अन्दर यदि चिन्ता नहीं है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह जवाब देते समय बतलायें कि इतने वर्षों में मौजूदा कानून के तहत कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की

गई है ? कितने लोगों का इन बड़े-बड़े व्यापारियों के साथ गुप्त-धंधा, भ्रष्टाचार या सांठ-गांठ चलता रहा है जिसके कारण हमारे निर्यात व्यापार में जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी है ? इतने वर्षों में देश के अन्दर अनेक कल-कारखाने लगे हैं लेकिन फिर भी देश का निर्यात व्यापार नहीं बढ़ पाया, इतना ही नहीं देश के अन्दर भी वे देश की जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं कर पाये। आज 20वीं शताब्दी में हर व्यक्ति चाहे वह गांव का साधारण आदमी भी हो, क्वालिटी की दृष्टि से बढ़िया माल खरीदना चाहता है, अगर किसी वस्तु की क्वालिटी अच्छी न हो, तो उसे नहीं खरीदता। इसलिये राष्ट्र में उत्पादित की जाने वाली वस्तुयें क्वालिटी में बढ़िया हों, टिकाऊ हों, तभी हम न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी वस्तुओं की खपत बढ़ा सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विदेश व्यापार में प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है। जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से घाटा बढ़ता जा रहा है। 1980-81 में यह घाटा लगभग 5 हजार करोड़ रुपये पहुँच गया था। उसके बाद बढ़ कर कभी-कभी साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये पहुँच गया। विदेश व्यापार में आज जो घाटा हो रहा है, यदि यह इसी प्रकार बढ़ता रहेगा तो इस देश की आगे क्या स्थिति होगी—यह बहुत गम्भीर बात है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिये कि किस तरीके से विदेश व्यापार के इस घाटे को कम किया जाय तथा विचार करके उस पर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। इस मामले को सदन में भी कई बार उठाया गया है, लेकिन दुख है कि सरकार इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। यह सरकार इस मामले में स्थिति को सुधारने में अक्षम सिद्ध हुई है।

मान्यवर, जहां तक क्वालिटी कन्ट्रोल का सवाल है—इस पर ऐसे बहुत से मामले हम लोगों के सामने आये हैं जिनको हमने इस सदन में भी उठाया है कई बार चर्चा के दौरान कहा गया है जब तक वस्तुओं की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक हम उनका निर्यात नहीं कर सकेंगे, और न वे विदेशी बाजार में बिक सकेंगी। मुझे एक मामला याद आ रहा है—एक बार इटली को चप्पलें भेजी गई थीं, जो वहां के लोगों को पसन्द नहीं आई, जिस तरह का माल वे चाहते थे उस तरह का माल नहीं भेजा गया था, जिसके कारण उन्होंने वह माल वापस कर दिया। इससे देश की प्रतिष्ठा गिरी, साख गिरी और आज जो घाटा हो रहा है उसका मूल कारण यही है कि जो वस्तुयें हम इस देश के बाहर भेज रहे हैं उनकी ठीक ढंग से जांच नहीं की जाती, अच्छी क्वालिटी की चीज नहीं भेज पा रहे हैं। यदि आगे भी यही स्थिति बनी रही तो विदेश व्यापार में हो रहे घाटे को हम कम नहीं कर सकेंगे।

मेरे पास ऐसी बहुत सी जानकारियां थीं जिनको मैंने समय-समय पर मंत्री महोदय को बतलाया है। आज मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी जो इंस्पैक्शन एजेन्सीज हैं, जब तक आप उनको दुरुस्त नही करेंगे, जब तक आप

इस बात को सुनिश्चित नहीं करेंगे कि जो बाहर भेजी जाने वाली चीजें हैं उनकी सही ढंग से जांच की जा रही है, अच्छी वस्तुयें बाहर भेजी जा रही हैं—तब तक देश का घाटा निरन्तर बढ़ता जाएगा जिसका देश की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और वह केवल सरकार के लिए ही नहीं, बल्कि देश की जनता के लिए भी बहुत घातक सिद्ध होगा। इसलिए जो इंस्पैक्शन एजेन्सीज हैं उनको स्ट्रीम-लाइन कीजिये, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कीजिये। आज एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह पैदा हो गई है कि जिन लोगों को किसी चीज की जांच का अधिकार दिया जाता है, वे लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, इसलिए जांच का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो भी जांच की जा रही है, वह सही जांच की जा रही है और जांच में लगे हुये लोग किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में संलग्न नहीं हो रहे हैं, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी पड़ेगी। अगर सरकार ने इस दिशा में कारगर कार्यवाही नहीं की, तो जो आपकी इंस्पैक्शन एजेन्सीज हैं, न वे सही काम करेंगी और न ही अच्छी क्वालिटी का माल आप विदेशों में भेज सकेंगे और अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही जैसा कि मैंने पहले बताया कि कभी 5 हजार और कभी 6 हजार करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष घाटा विदेश व्यापार में चल रहा है, यह चलता ही रहेगा। इस साल अभी कितने महीने हुये हैं और इनमें कितना घाटा हो चुका है यह मंत्री जी जानते होंगे और उसके सही आंकड़े वे दे सकते हैं। जनवरी से अब तक बहुत थोड़ा समय बीता है, चार महीने बीत चुके हैं और पांचवा चल रहा है लेकिन इस पीरियड में भी मंत्री जी को जानकारी होगी कि किस प्रकार से घाटा बढ़ रहा है और लगातार घाटे में वृद्धि होती ही जा रही है।

जहाँ तक इस विधेयक का प्रश्न है, इस विधेयक में अच्छी बातें कही गई हैं लेकिन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इन तमाम इंस्पैक्शन एजेन्सीज की कार्य-क्षमता को बढ़ाए और सरकार यह सुनिश्चित करे कि वहां पर ईमानदारी के साथ काम हो ताकि बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, उनको सुधारा जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): उपाध्याक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मेरी समझ में उस में कुछ बात नजर नहीं आ रही है सिवाय इसके कि इन्होंने मेम्बरों को बढ़ाने का काम किया है। आप यह देखेंगे कि विधेयक के अनुसार इंसपैक्शन कौंसिल की जो स्थापना हुई है, वह अधिनियम की धारा 3 के अधीन 1 जनवरी, 1964 को हुई थी और 20 वर्ष के बाद, मंत्री महोदय बतलाएंगे कि इन्होंने सिर्फ मैम्बरों को बढ़ाने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी श्री हरिकेश बहादुर ने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट घट रहा है और इम्पोर्ट बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि

एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अलावा, जो ट्रेड है उस ट्रेड में विश्व में हमारा शेयर केवल 1 परसेन्ट ही रह गया है जबकि जापान का आप देखेंगे कि 20 परसेन्ट शेयर है। इसका कारण क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं और मेरे पास तीन-चार रीसेन्ट एग्जाम्पिल्स हैं। टिंड फिश अमेरिका को जो भेजा था, वह लौटकर वापस आ गया। चीन को तम्बाकू भेजा था, वह लौट कर आप के पास भेज दिया गया। आप ने रूस को जूता भेजा था, वह भी लौटकर वापस चला आया और फिर रूस को आपने बासमती चावल भेजा, तो मालूम हुआ कि उसकी जगह पर परमल चावल भेजा गया और बासमती चावल नहीं भेजा और वह लौटकर चला आया। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पिल्स हैं। सब से बड़ी दिक्कत हमारे सामने यह आती है कि सरकार को मालूम है कि किस चीज का उत्पादन हमारे यहां कितना होता है। आप के यहां 20 लाख टन बासमती चावल का उत्पादन होता है और एक्सपोर्ट हो रहा है 40 लाख टन। तो यह एक साधारण अकल की बात है और सरकार इस बात को समझ सकती है कि जबकि उत्पादन केवल 20 लाख टन का है, तो 40 लाख टन का एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। इससे देश की प्रतिष्ठा गिरती है और सबसे बड़ा कारण यह है कि आप ने 36 प्राइवेट एजेन्सोज को एक्सपोर्ट करने का काम सौंप रखा है। अब प्राइवेट एजेन्सीज के सामने क्या मामला होता है। उनके सामने तो सबसे बड़ा मसला यह है कि उनका अपना मुनाफा कैसे हो चाहे देश की प्रतिष्ठा जहन्नुम में चली जाए और चाहे भारत का नाम बदनाम हो जाए। उनको तो मुनाफा कमाना है और इसलिए वे क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देती हैं। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे का सारा जो एक्सपोर्ट ट्रेड है, वह सरकार अपने हाथ में ले ले और प्राइवेट एजेन्सीज के ऊपर इसको न छोड़े। आपने 5-6 एक्सपोर्ट हाऊसेज को रिकगनाइज किया है और मेरे कहने में कोई अति नहीं होगी अगर मैं यह कहूं कि सरकार को भी उस में कोई शेयर मिलता है। सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इससे न सिर्फ हमारे देश को फाइनेन्शियेली घाटा हो रहा है बल्कि इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा खराब होती है। आप यह देखेंगे कि पहले विदेशों में जिनका कोई मार्केट नहीं था, वह इससे आगे निकल रहे हैं। हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं। हम तो रा-मैटीरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो हमारा बना बनाया हुआ सामान है, उसका हमारे पास कोई मार्केट नहीं रह गया है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल इन सारी चीजों के लिए यदि लाया जाता तो मुझे खुशी होती। लेकिन जो यह बिल है, और जो इसका उद्देश्य रखा गया है, उससे मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोई कारगर कदम उठेगा या यह बिल क्वालिटी कंट्रोल या इंसपैक्शन में सहायक सिद्ध हो सकेगा। इस बिल के द्वारा आप एक्सपोर्ट के मामले में कोई क्वालिटी कंट्रोल कर सकेंगे, ऐसी कोई चीज मुझे इसमें नजर नहीं आती।

13 hrs.

इसलिए में आग्रह करूंगा कि बजाए इस बिल को लाने के आप अपने प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त कीजिये

जिससे कि जो प्राइवेट एजेन्सीज हैं जो यह सब कुछ कर रही हैं उन पर अंकुश लगाइये । आप एक्सपोर्ट को अपने हाथ में लेकर ऐसा बिल लाइये जिससे कि भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़े, भारत की गिरती हुई साख बच सके । यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : I am really grateful to all those hon. Members who have participated in this discussion. Except, I think, Mr. Ram Vilas Paswan, all the Members who have spoken, have in principle agreed to this amending measure, because this is a laudable measure. During the last few years in the operation of this Act, certain lacunae have come to our notice. We have tried to fill up those lacunae by this amending measure.

Also, there are some provisions which we have brought in, to make it more stringent. So, it is quite natural that all those Members who have studied this amending Bill have given their full support to this measure.

Of course, while making suggestions in the course of their speeches, they were no doubt critical on some areas; more particularly, I think all of them have mentioned about the performance of the inspection agencies; and they required us to make them more useful.

I do not grudge this sort of critical opposition or suggestions, because I feel the whole approach of our friends here, and the motivations is to give greater emphasis on measures of quality control and pre-shipment inspections, in the interest of Indian goods in the overseas markets. So, that is the idea, keeping which in mind they have given such suggestions. I believe these are very useful suggestions, and Government is going to be benefitted from them.

I must also say that while making their speeches, in some areas, they have gone beyond their limits, which have got no relevance at all with the proposed measure. If time permits, I will of course go into those matters also.

For example, Mr. Ram Vilas Paswan said it ; and also my friend Mr. Chakraborty who initiated the discussion, said that we produce only one crore kilograms of Darjeeling Tea, but we are exporting four crores kilograms of it. He says that we produce only a certain amount of Basmati rice, but we are exporting more than that. I do not know what is the source of their information. But these are some of the things based on misinformation, which I would like to clarify in the course of my speech.

Mainly, 3 or 4 pointed questions have been asked. They expect some answer to them. One of these is : why not cent-per cent coverage ? As everybody was speaking, we have taken under quality control, about 800-odd items ; but they ask : why not cent-per cent of the items ?

The hon. Members were critical about the self-certification scheme. Some of them say that it should be abolished.

Thirdly, they also wanted to know the action we have taken against the erring exporters, and also delinquent officers—what measures we have taken against them during the last 20 years. They have also raised the question about the performance of these export inspection agencies. So, these are the main, broad and pointed questions which I would like to reply, in short.

About the coverage of more items under Act, there is no doubt that so far, 875 items have been brought under the ambit of compulsory quality control and pre-shipment inspection. My friend Mr. Verma is not here. He

said that only 10% of the entire export was coverd. It is not a fact. This alone itself constitutes 42 per cent of the country's total export and represents major items in engineering, food, agriculture, chemicals, allied products, footwear and components, jute products, carpet, etc. Besides this compulsory quality control and preshipment inspection of the items notified under this Act, there are other statutory regulations, which, I think the hon. members should know, which govern quality of goods for export. For example, Textiles, Committee Act, 1963, Drugs and Cosmetics Act 1940, Essential Commodities Act 1955, Prevention of Food Adulteration Act 1955, Agricultural Products (Grading and Marking) Act 1937, ISI (Certification Mark) Act 1952, etc. and these also cover about 20 per cent. You will see that the percentage is as high as 60-70. We are not contented with it. What the hon. members have in their mind, we are also approaching towards that. We have asked our Export Inspection Council to go into this question and see what more items can be brought under this regulation and they should suggest to us. I think they should not have any apprehension on this measure because we are also approaching towards that.

As regards self-certification, most of the members said that it should be abolished. We have adopted this scheme on the very solid recommendation made by a high powered technical committee which went into this aspect and they suggested to introduce this scheme. Government has accepted this suggestion and we have introduced this scheme. In May 1981, the scheme was initially extended to engineering industry and so far only 18 engineering units have been given recognition under this scheme. The self-certification facilities are extended to units for a period of only one year ; and after that a scrutiny is made and if they fulfil certain criteria then only they are extended to them. Before granting self-certification facilities, an inter-departmental panel consiting of senior technocrats in the Department of ISI, Defence Inspection, Director of Industries, DGTD, Development Commissioner, Small Scale Industry, etc. examine the request of units for granting self-certification. It is only granted to those units who have been cleared by the high powered technical panel. Here I may be permitted to say that it is no good to suspect everybody ; there are good people also. But, in general, if you say, everybody is unscrupulous, everybody is bad, this is not a very good approach, because, after all, they have their own stake for exporting things ; and we must rely at least on good persons. One hon. Member who is not here. He has made wild allegations. He said, "After the introduction of this scheme, a number of complaints has gone up unlimited." According to the information with me, since May 1981 till date, only one complaint under this scheme was received on the foreign buyer in respect of ceiling fan exported by one unit. A detailed examination was immediately made and it revealed that the complaint was that canopies and regulators of some of the ceiling fans were received in broken condition and in some of the boxes cortents were also missing. In fact, there is nothing technicality involved here ; quality is not also involved. But, anyhow, the units which have been granted self-certification facilities are being audited periodically by the officers of the Export inspection agency headed by an Additional Director to ensure that the scheme is administered by the units in accordance with the prescribed rules.

Now, we have also under this scheme a new Section 11B of the Act which will ensure that any malpractice committed by any unit will be dealt with through stringent measures.

Now, another area where most of the hon. Members have shown anger is the private inspection agencies. In fact, Shri Vyas anl Shri Rajesh Kumar Singh—nobody is here—said that this private inspection agencies recognised by the Government under the Act,

should be dispensed with and all the inspections should be carried by the Government agencies. I think Mr. Paswan also suggested the same. Now, here I would like to assure my friends that these private inspection agencies were recognised only in those fields and items for which the expert inspection agencies did not have the necessary expertise. Where are we to go then ? If we do not have the necessary expertise naturally we have to fall on somebody who has got it. In some cases only we have allowed this. It has since been decided that the private agencies will be recognised by the Government for the items for which we do not have the expertise, for carrying out preshipment inspections.

Again, there is also the question whether this should be allowed to be done by the private inspection agencies for some more time. This question was entrusted to a high powered commtttee. This committee also suggested continuing of such inspection agencies. The recommendations of the committee have also been accepted. Hon. Members may be able to notice, perhaps the new section 11(b)(i) in the Act, will take care of the unscrupulous employees of the private inspection agencies, and there is provision for punishment both imprisonment as also fine.

I think now will take the question of my friend Mr. Paswan, when he asked what action is taken against the exporters and the inspectors, when complaints come, during the last 20 years. This is also a fact that because of certain lacunae and defects in the Act so far we have not been able to take any action ; but now we will be do it after passing of this amending Act. However, I would like to are with the hon. Members some of the facts which I have with me. During the period 1979 to 1983 with the sanction of the Director (Inspection and Quality Control) as many as 33 complaints were filed against the erring exporters in the court and 12 were fined, four have been discharged, and some cases are pending the court as well. In one case an appeal has been filed in the hon. High Court of Kerala.

I think he also mentioned, and Mr. Rajesh Kumar Singh also had drawn our attention to the inspection of sub-standard chappals worth about Rs. 60 lakhs exported to Italy. While it is a fact that a complaint was received from the Italian firm, as soon as the complaint was received by the Government the matter was handed over to the Central Bureau of Investigation. The CBI have investigated the case and they have launched prosecution against the exporter and the Inspection officer. Therefore, we have taken prompt action against the erring exporters as also the delinquent officers, whenever we have received the complaints.

About the officers also I have some figures with me. While six officers have been prosectuted, during the period 1979-1983, one has been convicted, and five cases are pending in the courts, and one case an appeal has been filed in the hon'able High Court of Kerala.

In addition to that, departmental action has also been taken against the officers. 12 officers have been removed from service by the Director, 9 officers have otherwise been penalised departmentally. Departmental inquiries against 21 officers are in progess. The CBI is also investigating against two officers in the rank of Joint Director for alleged possession of assets disproportionate to their known source of income.

Not only that. In order to keep watch on the officers, Vigilance cell has been set up one each at Bombay, Cochin, Calcuttu, Delhi and Madras with the Central Cell in the office of the Director. Technical Audit Cells have also been set up at the headquarters of the Inspection Agencies at Bombay, Cochin, Calcutta, Delhi and Madras which are responsible to carry out the super checks on the inspected consignments at the port of shipment

to detect whether any manipulation of the consignments has been made by the exporters after inspection.

Another pointed question was asked about the performance of the export inspection agencies. One hon. Member was saying that it is shameful that till today only 5 agencies have been created. It is not a fact. While the Export Inspection Council has been established by the Central Government in January, 1956, five export inspection agencies each at Bombay, Calcutta, Cochin, Madras and Delhi have been set up by the Government on 1.2.1966. These agencies have 62 sub-offices throughout the country with total manpower of about 2340 which includes technical hands. The appointment to the post of Director, Inspection and Quality Control, is made by the Central Government keeping in view his function of overall administration and supervision of the schemes of quality control and pre-shipment inspection. Here, Prof. Chakraborty has mentioned a particular case and wanted to know whether the Director is technical or non-technical, whether his appointment is under the rules and regulations. Every aspect had been gone through. There had been no violation of rules in the matter of appointment and confirmation of the present incumbent in the post of Director. So, the approach adopted by the hon. Member is not a correct one.

I have already submitted that a critical review of the working of the Export Inspection Council and Export Inspection Agencies have been made in 1982 by a High Powered Committee. Pursuant to the recommendation of the Committee, a number of measures have been taken for up-dating and upgrading the inspection standards, training programme for the manufacturers and exporters specially in the small scale sectors, upgradation of quality levels in the industries, analysis of quality complaints, application of modern concepts and techniques for quality control, utilisation of mass media for projecting the quality of the Indian products and lastly to generate quality culture and consciousness amongst the exporting community. The Quality Development Cell for this purpose has already been set up in Madras.

The Members will be glad to know that with the improvement in the functioning of the Export Inspection Council and Agencies, the complaints on quality for the consignments exported by these Agencies have come down appreciably. On the average about 2.5 lakh consignments are inspected by the Agencies per annum. While during 1979-80, 312 complaints were received, the same has come down to 63 during April—December, 1983. For the purpose of investigation, taking appropriate action against the erring exporters and officers, as well as to effect necessary improvements to arrest such complaints, Regional Quality Control Cells at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras have been constituted under the Chairmanship of JCCI&E of the respective region.

So, in general, these are the important points which I have tried to explain. Besides these, there are some minor points which I have already said I will try to answer and which are not facts. Satyasadhan Babu is not here. His wild allegation was that we are producing 10 million kgs. of Darjeeling tea—which is a fact—and we are exporting around 40 to 44 million kgs. of Darjeeling tea. Our average annual production of Darjeeling teas is around 12 million kgs. Of this, we export only around 80 per cent, i.e., approximately ten million kgs. So, it is definitely an incorrect statement to say that we are exporting more Darjeeling tea than is being produced. However, most of the Darjeeling tea is exported from India in bulk in unblended form. Mr. Chakraborty will be interested to know as to how it is heppening. I do not deny this, but how it is happening, you also should know it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : You know but you are to

take action, that is the trouble. You know, but I cannot take any action, you are to take action.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : You are a reputed lawyer, you just help me.....*(Interruptions)*.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : When I say something particular with regard to another public sector undertaking asking for an enquiry, he says nothing has been found, I do not know anything, no opportunity has been given to me. And who enquired ? It was the management against whom charges were made. I made the charges, so he was asked to explain his conduct. He said he was innocent and the Minister copied it to me that he is innocent.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : I look into it. When you send me something I am responsible for it, I will look into it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I have already written to you a long letter.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : What I was telling is that the Darjeeling teas have earned a world wide reputation as the "Champagne of teas" on account of their unmatched flavour. On account of the fact that most of our Darjeeling tea are packeted and marketed abroad, we have no control over the manner or percentage of blending Darjeeling tea with other tea. So, we send it in unblended form and the people there themselves blend it. How much content of Darjeeling tea is there, even that is also not known to us. It is a fact that in the international market today there are several brand names selling as Darjeeling tea which contain only a small amount of Darjeeling tea—the percentage is unspecified on the consumer packets. Hence it is commonly known among the international tea trade that the total quantity of teas sold in the name of Darjeeling far exceeds the total qnantity of Darjeeling tea produced in India.

In order to check this situation, we are trying to ensure that the entire production of Darjeeling tea should be exported as far as possible in value added form, i.e., tea packets, tea caddies, etc. This is the only alternative. This would prevent the pure Darjeeling tea from being blenned with other poorer quality tea and sold under the name of Darjeeling tea. A Marketing Society consisting of producers of the Darjeeling area has recently been set up under the Tea Board to plan out a marketing startegy for Darjeeling tea to ensure optimum price realisation for the producers and the preservation of the unique qualities of Darjeeling tea. That is why there is no question that India is in any way attempting to export non-Darjeeling tea as Darjeeling tea. It is absolutely a wrong statement made by the hon. Member.

Now, Sir, Mr. Satyasadhan Chakraborty has mentioned about Basmati rice that we are exporting more of it than what we are producing in the country. This is not a fact. The Basmati rice produced in our country mainly in Haryana, Punjab and UP on the rough estimate would be of the order of 2.5 to 3 lakh tonnes.

The export of Basmati rice has been on the Open General Licence and exports in the last few years have been as under :

In 1976-77 it was 20,8000 ; in 1977-78 it was 10,000 tonnes ; in 1978-79 it was 67,100 tonnes , in 1979-80, it was 47,000 tonnes and in 1980-81, it was one lakh 37,000 tonnes. Only in 1981-82, I may be a little correct in the statement, I find the export is a little more than three lakh tonnes. It would thus be seen that exports are not more than what is estimated to be produced excepting for the year 1981-82, in which year due to lack of export in the previous years the country had a sufficiently high stock of Basmati rice available for export. But seeing all these we have taken action now. *(Interruptions)* I would say we have taken action

whenever complaint has come to our notice.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा चार्ज था कि बासमती चावल के बदले परमल चावल को बासमती कहकर भेजा गया था। यह ठीक है या नहीं ? अमेरिका में माल भेजा गया वह लौटा दिया गया, चप्पल और तम्बाकू भेजा गया, वह लौटा दिया गया।

आपके पास फाइंड आउट करने की ऐजन्सी है, आप क्यों नहीं पता करते ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : What we state, we state on facts. So far as these complaints are concerned, we have not received anything. But we have changed the entire system now. From now onwards we have said that only the Government agency will inspect. Initially on the advice of the people who were importing this rice, some private agencies were there to certify. But now we have abolished this and only the Government agency will certify it.

Now I would say a few words about Cardamam and other things. Of course, that does not form part in this discussion, but still I would say that we have taken steps to see that this situation does not recur. No doubt the production was falling because of the drought. But now we are taking steps to see that the production increases.

These are all the points that I think have been raised and I have tried to answer all of them.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill to amend the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 2 to 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 9 were added to the Bill.

Clause 1—(Short title and Commencement)

MR. DEPUTY-SPEAKER : In Clause 1, there is a Government Amendment.

Amendment made :

Page 1, line 4, —

for "1983"

substitute "1984" (2)

(SHRI NIHAR RANJAN LASKAR)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That Clause 1, as amended, stand, part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula

Amendment made

Page 1, line 1,—

for "Thirty—fourth" *substitute*— "Thirty—fifth" (1)

(SHRI NIHAR RANJAN LASKAR)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR ; Sir, I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

13.32 hrs.

MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES (AMENDMENT) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, we go to the next item—Monopolies and Restrictive Trade Practices (Amendment) Bill.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGAN NATH KAUSHAL) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move* :

"That the Bill further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, and the Companies Act, 1956, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

---

*Moved with the recommendation of the President.

Sir, the working of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, which has been on the Statute-Book for more than 13 years now was reviewed by the High-Powered Export Committee in 1977-78. This Committee had suggested a number of improvements for the better working of this important legislation. In April, 1982, while introducing a short Bill for amending certain provisions of this Act, I had assured the House that a comprehensive Bill for amending the Act, both in the light of the recommendation of the High-Powered Expert Committee and in the light of the experience gained in the working of the Act over the years, would soon be introduced in the Parliament. In fulfilment of this assurance, the present Bill is being brought, which provides not only for streamlining the existing provisions of the law dealing with concentration and monopolies but also incorporates some new provisions to curb monopolies and unfair trade practices, the latter particularly being intended to give greater protection to the consumer.

The amendments proposed in the Bill coupled with the amendments introduced in the Act in August, 1982, seek to strike a balance between the twin objective of checking concentration of economic power to the common detriment and encouraging growth in accordance with our national goals and aspirations. Thus, while the conceptual ramifications of the definition of "undertaking", "inter-connected undertaking", "goods", "value assets" etc. have been more clearly spelt out, certain incongruities arising out of the interpretation of the present provisions have removed by the provisions of the Bill. The present definition of 'undertaking' is such that undertakings controlled by an investment company remain outside the perview of the Act because investment companies, as the present definition of 'undertaking' stands, are not undertaking within the meaning of the Act. Similarly, the present definition of 'undertaking' does nat bring within its ambit a new